

संपादकीय

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

गाजा पट्टी पर इजराइल के अविश्वसनीय हमले की शुरुआत के बाद से, संयुक्त राज्य अमेरिका ने — पहली बार — 25 मार्च को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव को अपनाने की अनुमति दी, जिसमें रमजान के महीने के दौरान युद्धविवारण की मांग की गई थी। इसमें दलों द्वारा सम्मान किया जाता है। अब तक, इसने औपचारिक यूएनएससी प्रस्तावों के खिलाफ अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करके, गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई को रोकने के सभी अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को अस्वीकार कर दिया था। क्या अमेरिका का यह कदम यहूदी राज्य के प्रति उसके दृष्टिकोण में बड़े बदलाव का संकेत देता है? या यह महज इजरायली पोर पर एक रैप है? इन सवालों का जवाब देने के लिए, अमेरिका-इजरायल संबंधों के बुनियादी सिद्धांतों के साथ-साथ इजराइल पर हमास के 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमले की भयावहता के मनोवैज्ञानिक प्रभाव की सक्षेप में जांच करना उपयोगी होगा। साथ ही, गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई के मानवीय परिणामों के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की बढ़ती आंतरिक और बाहरी शर्मिंदगी पर भी गौर करना जरूरी होगा। लेकिन पहले, आइए यूएनएससी प्रस्ताव के कुछ पहलुओं पर नजर डालें। यूएनएससी प्रस्ताव 2728 का प्रस्तावना भाग, जिसे परिषद के 15 सदस्यों में से 14 ने अमेरिका के अनुपस्थित रहने के साथ अपनाया था, संघर्ष के सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करने की मांग करता है। यह एक नियमित सूत्रीकरण है जो संघर्ष स्थितियों पर लगभग सभी प्रस्तावों में पाया जाता है। यदि इस सूत्रीकरण की जांच करने की आवश्यकता नहीं

भारतीय राजनीति में विषाक्त पुरुषत्व अभी भी व्याप्त

आदित्य

हम सभी को भारतीय होने पर गर्व है। भारत एक ऐसा देश है जो हर चीज में भगवान को देखता है चाहे वह इंसान हो, पेड़ हों, पत्थर हों, पानी हों, सूरज हों, धरती हों, हवा हों या जानवर हों। यह हमारी जुबान पर होने वाला एक सामान्य सवाद है। लेकिन जब सुरक्षा और फैसले की बात आती है, तो हमारे देश में महिलाएं कहाँ खड़ी हैं? राजनेताओं को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि वे कितनी बार सार्वजनिक मंचों पर अपनी स्त्रीद्वेषी मानसिकता को साबित करते हैं। ऐसा क्यों है कि उनकी मानसिकता अभी भी अहंकार और पुरुषवाद से घिरी हुई है? अगर महिलाएं पुरुषों का समर्थन न करने का फैसला कर लें तो क्या वे चुनाव जीत सकती हैं? कभी नहीं! उन्हें यह समझना चाहिए कि महिलाएं पुरुषों से अधिक संख्या में हैं और धैर्यपूर्वक लंबे समय तक अपनी बारी का इंतजार करते हुए अपने मत का प्रयोग करती हैं। महिला मतदाताओं में 55 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। प्रचार के दौरान नेता महिला मतदाताओं के सामने झुकते हैं और उन्हें हमारी माताएँ, हमारी बहनें कहते हैं, लेकिन एक बार चुनाव समाप्त हो जाने और वे विधायिकाओं में आ जाने के बाद, वे नारी शक्ति को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि वे छूट जाते हैं और उनकी संबंधित पार्टी का नेतृत्व इस तरह की टिप्पणियों की निंदा करने तक की जहमत नहीं उठाता। नवीनतम टिप्पणियाँ एक कांग्रेस नेता की थीं और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक रूप से एक महिला नेता की थीं, जो आधिकारिक प्रवक्ता भी हैं। मंडी वह जगह है जहां से कंगना रनौत चुनाव लड़ेंगी। इसे छोटा काशी के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस नेता एचएस अहीर और सुप्रिया श्रीनेत ने अपमानजनक अर्थ में शम्भुदीश शब्द का इस्तेमाल किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और तो और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इसकी निंदा करने या नेताओं की खिंचाई करने की भी जहमत नहीं उठाई। यहां तक कि जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उनकी प्रतिक्रिया थी, शशाप किस कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। क्या वीजेपी ने तब कार्रवाई की जब उनके नेताओं ने ममता के खिलाफ टिप्पणियां की? यह एक हास्यास्पद तर्क है। वे यह कैसे कह सकते हैं कि हमें कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाजपा ने कार्रवाई नहीं की है? क्या वे यह कहना चाहते हैं कि वे बुरे हैं और हम भी कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका नेतृत्व कई वर्षों तक इंदिरा गांधी और बाद में सोनिया गांधी ने किया, जो अभी भी सर्वोच्च शक्ति केंद्र हैं और अब प्रियंका गांधी उभर रही हैं। वह स्थिति, प्रियंका अक्सर कहती है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो फिर पार्टी के भीतर ऐसे तत्वों के खिलाफ लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जाए? ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सबसे वरिष्ठ नेताओं ने भी, जिन्होंने महिलाओं के लिए वोट मांगे थे और भीख मांगी थी, बाद में अपमानजनक टिप्पणियां की। 2014 में, तत्कालीन अस्सी वर्षीय नेता और समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने राज्य में चुनावों से पहले एक रैली को संबोधित करते हुए बलात्कार के लिए मौत की सजा का विरोध करते हुए कहा था, लड़के लड़के हैं, गलती हो जाती है। गलतियाँ की जा सकती हैं।) वह यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, इश्ल़कियां पहले दोस्ती करती हैं। लड़के-लड़की में मतभेद हो जाता है। मतभेद होने के बाद उसे रेप का नाम दिया गया है। लड़कों से गलती हो जाती है। क्या रेप केस में फांसी दी जाएगी?" इसी तरह महिला आरक्षण विध आकर्षक नहीं हैं... मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा, उनकी टिप्पणी थी। स्नेह फैलाने के नाम पर लोकसभा में पीएम को गले लगाने वाले राहुल गांधी ने बाद में टिप्पणी



बिहार की राजनीति का ‘चिराग’ संभावना का वाहक

लालत
सरहद देश

खुद का प्रधानमंत्रा नरन्द्र मादा का हनुमान बताने वाले युवा नेता चिराग पासवान इन दिनों बिहार की राजनीति में लाइमलाइट में हैं। राजनीतिक कौशल एवं प्रभावी रणनीति के तहत तेजी से अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूती देते हुए बिहार की राजनीति का 'चिराग' संभावना का वाहक बन रहा है। चिराग पासवान सक्षम जनप्रतिनिधि के साथ-साथ मौलिक सोच एवं संवेदनाओं के प्रतीक हैं। उन्हें सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी होकर प्रासंगिक एवं अप्रासंगिक के बीच भेदरेखा बनाने एवं अपनी उपस्थिति का अहसास कराने का छोटी उम्र में बड़ा अनुभव है जो भारतीय राजनीति के लिये शुभता का सूचक है। लोकतंत्र का सच्चा जन-प्रतिनिधि वही है जो अपनी जाति, वर्ग और समाज को मजबूत करने के साथ देश को मजबूत करें। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' की लड़ाई लड़ने वाले चिराग 14 करोड़ बिहारियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये प्रतिबद्ध हैं। आगामी लोकसभा चुनाव-2024 चिराग का सशक्त एवं उम्मीदभरा राजनीतिक भविष्य उजागर करते हुए बिहार के शीर्ष नेतृत्व की ओर अग्रसर करे तो कोई आश्चर्य नहीं। इस बात के

दुविधा

सार्वजनिक खरीद नीतियां कुछ राज्यों के लिए प्रासंगिक हैं यह उन्हें अन्य क्षेत्रों तक भी बढ़ाय जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र आर्थिक स्थिरता, रोजगार के अवसरों पर्यावरणीय प्रभाव और सामाजिक आर्थिक असमानताओं से संबंधित बहुआयामी संकटों से जूझ रहा है वित्त वर्ष 15 और वित्त वर्ष 24 के बीच कृषि में 3.55: की वृद्धि देखी गई। 45.8: कार्यबल वाले कृषि क्षेत्र की यह सुरक्षा वृद्धि 2012–13 और 2018–19 के बीच फसल आय में खतरनाक गिरावट में परिलक्षित होती है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यालयान संवालय द्वारा जारी

नवीनतम बड़े पैमाने पर स्थिति
मूल्यांकन सर्वेक्षण आंकड़ों के
अनुसार, फसल की खेती से
वास्तविक आय में अखिल भारतीय
स्तर पर 1.2: की गिरावट आई है,
जबकि कृषि परिवारों की कुल आय,
जिसमें पशुधन और पशुधन से कमाई
शामिल है। वेतन में प्रति वर्ष 3:
की मामूली वृद्धि हुई। विभिन्न राज्यों
में कृषक परिवारों की आय के स्तर
में महत्वपूर्ण असमानता है। उदाहरण
के लिए, 2021–22 की कीमतों में,
पश्चिम बंगाल में एक कृषि परिवार
की औसत मासिक आय लगभग
7,838 रुपये प्रति माह है, पंजाब में
लोग औसतन लगभग 31,089 रुपये

प्रति माह कमाते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर प्रति कृषि परिवार की कुल आय से प्राप्त आय दशमांश की जांच करने पर, डेटा से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में, केवल 2.86: कृषि परिवार शीर्ष आय दशमलव में स्थित हैं, जबकि पंजाब में यह अंकड़ा 28.4: है। पंजाब की समृद्धि का श्रेय काफी हद तक इसकी सुनिश्चित और खुली खरीद प्रणाली को दिया जाता है। एमएसपी एक ऐसी मंजिल तय करने के लिए है जो कीमतों को इस सीमा से नीचे गिरने से रोकती है। पंजाब और हरियाणा भारत की खाद्यान्न ख्रीट प्रणाली में अग्रणी थे। गढ़

कहा ज

सुनिश्चित करने के लिए व्यापक राजनीतिक ध्यान दिया गया है कि इन राज्यों के किसानों को योजना के तहत व्यापक कवरेज मिले। वर्ष 2021-22 के लिए पंजाब में उत्पादित धान का 97% से अधिक एमएसपी पर खरीद गया। दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल (14.1%) और उत्तर प्रदेश (28.7) जैसे प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में खरीद काफी कम थी। 2023 के खट्टीफ सीजन के दौरान, सामान्य धान का एमएसपी 2,183 रुपये प्रति विवर्तन था। अबटूबर से दिसंबर के फसली महीनों के दौरान, पंजाब और दिरिगणा में खत्ते बाजारों में धान

की थोक कीमत क्रमशः 2,634 रुपये और 2,239 रुपये तक बढ़ गई। इसके विपरीत, पश्चिम बंगाल में, जहां सार्वजनिक खरीद न्यूनतम है, धान की थोक कीमत 2,126 रुपये प्रति किलोटल है, जो एमएसपी से कम है। इसके अलावा, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत धान की आर्थिक लागत से कम 29 रुपये प्रति किलोग्राम पर चावल उतारने से खुले बाजारों में कीमत कम हो जाती है, जिससे उन राज्यों में किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जहां एमएसपी कृतरेज कम है।

पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी शीर्ष स्थान पर

आसिप

अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में से 10 पर अपनी निर्विरोध जीत के साथ, सीमावर्ती 19 उपरा या एक राज्य होना। आठ पूर्वोत्तर राज्यों की 25 लोकसभा सीटों के अलावा, अरुणाचल प्रदेश की शेष 50 विधानसभा सीटों और



राज्य में भाजपा की आसन्न जीत शेष पूर्वोत्तर राज्यों में पार्टी को बढ़ावा दे सकती है। राज्य की दो लोकसभा सीटों – अरुणाचल पश्चिम और अरुणाचल पूर्व – के लिए विधानसभा उम्मीद और संसद

सिविकम की 32 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। कुल 25 लोकसभा सीटों में से 14 असम में हैं, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा (2 सीटें) और नागालैंड विधान

और सिक्किम (1 प्रत्येक) हैं। पूर्वोत्तर की 25 लोकसभा सीटों पर भाजपा पहले से ही लाभप्रद स्थिति में है, क्योंकि पार्टी के पास वर्तमान में असम (9), त्रिपुरा (2), अरुणाचल प्रदेश (2) और मणिपुर (1) में 14 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास चार हैं – असम में 3 और मेघालय में 1। शेष सात सीटों में से, असम की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, नागालैंड की नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपी), मिजोरम की मिजो नेशनल फ्रंट, मेघालय की नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी), मणिपुर की नागा पीपुल्स फ्रंट और सिक्किम की सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) के पास एक सीट है। प्रत्येक। असम में एक सीट निर्दलीय के पास है। अरुणाचल प्रदेश, असम, असम, असम

मुख्यमंत्री खांडू ने 2016 में अरुणाचल प्रदेश में पहली भाजपा सरकार बनाई, जब उन्होंने कई विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी और पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (पीपीए) का गठन किया। इसके बाद, खांडू सहित अधिकांश पीपीए विधायक भाजपा में शामिल हो गए। 2019 में, भाजपा ने 41 सीटें जीतीं, जनता दल (यूनाइटेड) ने सात सीटें हासिल कीं, नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ने पांच सीटें हासिल कीं, कांग्रेस ने चार सीटें हासिल कीं और पीपीए ने एक सीट जीती जबकि दो सीटें निर्दलीयों के पास गईं। जदयू के सभी सात विधायक और पीपीए का एकमात्र विधायक बाद में भाजपा में शामिल हो गए। इस साल फरवरी में एनपीपी के दो और कांग्रेस के तीन विधायक रीतेंगे में शामिल होंगे।

पाला बदलने के बाद अरुणाचल में बीजेपी विधायकों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। हालांकि मुख्य विधेयकी दल कांग्रेस ने इस बार 34 उम्मीदवारों की घोषणा की है और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली एनपीपी ने अरुणाचल में विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन वास्तव में कांग्रेस के 19 और एनपीपी के 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। दो दलों ने या तो अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया या अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित ए.पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, पीपीए 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी 1 सीटें पर चुनाव लड़ रही हैं।

जबकि लोक जनशक्ति पार्टी
(एलजेपी) ने 4 सीटों पर उम्मीदवार
जतारे हैं। 1 सीट पर चुनाव लड़
रही है। प्रमुख भाजपा नेताओं में से
एक और असम के मुख्यमंत्री हिमंत
बिस्वा सरमा को अक्सर यह कहते
हुए सुना जाता है कि उन्हें विश्वास
है कि एनडीए पूर्वोत्तर क्षेत्र की 25
लोकसभा सीटों में से 22 पर जीत
हासिल करेगा। सरमा ने दावा किया
कि क्षेत्र में भाजपा और उसके
सहयोगियों का शायद ही कोई
मुकाबला है। सीएम सरमा ने रविवार
को एक पार्टी बैठक में कहा, "चुनावी
लड़ाई हमारे उम्मीदवारों के बीच
सबसे अधिक अंतर से जीतने के
लिए होगी, और मैं इसे लेकर संतुष्ट
नहीं हो रहा हूं। एक अन्य वरिष्ठ
नेता और केंद्रीय मंत्री सर्बनन्द
सोनोवाल ने भी कहा कि पूर्वोत्तर
उन चारी जीतों की ओर मैं अपना

भूमिका निभाएगा। सोनोवाल ने कहा, असम की 14 सीटों में से हमारा (भाजपा) 12 सीटें जीतने का लक्ष्य है और पूर्वोत्तर राज्यों की 25 सीटों में से हम 22 सीटें जीतेंगे। त्रिपुरा में भी, भाजपा इस बार लाभप्रद स्थिति में है, क्योंकि प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मन के नेतृत्व वाली आदिवासी—आधारित टिप्परा मोथा पार्टी (टीएमपी), जिसने 2019 के चुनावों में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, न केवल उसकी सहयोगी बन गई है। बल्कि आगामी चुनावों के लिए संयुक्त रूप से प्रचार भी कर रहे हैं। साल भर की चर्चा के बाद, 2 मार्च को केंद्र और त्रिपुरा सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, आदिवासी—आधारित पार्टी इस साल 7 मार्च को भाजपा के नेतृत्व वाली समझौते समर्पण में शामिल हो सकती है।

